एस. एस. संधावलिया से पहले सी. जे. और एस. पी. गोयल

पारस राम,-*अपीलकर्ता।*

बनाम

कमलेश—*प्रतिवादी।*

1980 का एफएओ नंबर 70-एम।

24 सितंबर, 1981।

हिन्दू विवाह अधिनियम (1955 का *XXV*) - *धारा* 13(1) (i-a)-पत^- ** पति द्वारा विवाह के विघटन के लिए - पत्नी द्वारा लिखित कथन में *बचाव में पति द्वारा व्यभिचार की दलील उठाना - ऐसी दलील को मुद्दा नहीं रखा गया - लिखित कथन में व्यभिचार का मात्र आरोप - क्या* धारा के *अर्थ के भीतर क्रूरता है* 13 (1) (टी-ए)।

यह माना जाता है कि जीवनसाथी के खिलाफ व्यभिचार का झूठा आरोप कानून की नजर में क्रूरता के बराबर है। हालांकि, इससे यह अनुमान लगाना बहुत दूर की बात होगी कि व्यभिचार का आरोप, चाहे साबित हो या नहीं, बीवी स्वयं कानूनी क्रूरता के गणितीय समकक्ष होगा। यह कानून नहीं है, और संभवतः नहीं हो सकता है कि व्यभिचार का तथ्यात्मक रूप से सच्चा आरोप, चाहे वह अन्यथा किया गया हो या बचाव में, लिखित बयान में क्रूरता के समान होगा। इस क्षेत्र में इस तरह के आरोप की सच्चाई या अन्यथा मामले की जड़ है। इसलिए, व्यभिचार के आरोप को कानूनी क्रूरता के रूप में समझा जाने से पहले इसे तथ्यात्मक रूप से गलत साबित किया जाना चाहिए। उजागर करने के लिए, यह व्यभिचार का एक झूठा झूठा आरोप है जो कानूनी क्रूरता के बराबर होगा और उस प्रकृति का एक सच्चा आरोप संभव नहीं है जो अपमानजनक पति या पत्नी को कार्रवाई का कोई कारण नहीं दे सकता है। एक बार ऐसा हो जाने पर। यह प्राथमिक प्रतीत होता है कि व्यभिचार का ऐसा कोई भी आरोप परीक्षण के लिए नट होना चाहिए और यह केवल तभी होता है जब इसकी मिथ्याता या अन्यथा निर्धारित किया जाता है कि कोई कानूनी परिणाम उससे प्रवाहित हो सकता है। इसलिए, यह माना जा सकता है कि केवल अपने आप में लगाया गया आरोप और वह भी कानूनी अभिवचनों में बचाव के माध्यम से लगाया जाना कानून की नजर में कानूनी क्रूरता बन जाना चाहिए और *स्वत* तलाक का आधार होना चाहिए।
((पैरा 5)।

श्रीमती जीवसन लता वि. *कृष्ण कुमार,* 1979 *वर्तमान लॉ जर्नल* [509] को खारिज कर दिया गया।

मैं *श्री ओपी गुप्ता के आदेश से प्रथम अपील, अपर नियुक्त-*
जुडे नारनौल ने दिनांक 14 फरवरी, 1/980 को *लागत सहित नीति को खारिज कर दिया। ''*

अशोक कुमार अग्रवाल, अधिवक्ता, ^ *अपीलकर्ता।*

चंद्रसिंह अधिवक्ता, *प्रतिवादी के लिए।*

निर्णय

एस. एस. *संधावद्लिया, सी.जे.*

1. क्या एक लिखित बयान में बचाव में किए गए पति या पत्नी द्वारा दूसरे के खिलाफ व्यभिचार का आरोप लगाया जाएगा, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 (1) (10) के अर्थ के भीतर, क्रूरता के रूप में माना जाएगा, यह मुख्य प्रश्न है जिसके लिए इस संदर्भ की आवश्यकता है।

2. इसके बाद प्रकट होने वाले कारणों के कारण (** ट्रायल कोर्ट को रिमांड, यह केवल पूर्वोक्त मुद्दे से संबंधित तथ्यों को संक्षेप में विज्ञापित करने के लिए पर्याप्त है। अपीलकर्ता-पति ने अपनी पत्नी के खिलाफ हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत अन्य बातों के साथ-साथ क्रूरता और परित्याग के आधार पर विवाह के विघटन के लिए याचिका को प्राथमिकता दी थी। प्रतिवादी-पत्नी ने एक लिखित बयान दायर किया और बाद में उसमें संशोधन किया। इसमें अपीलकर्ता-पति द्वारा किए गए तथ्यात्मक कथनों से इनकार करते हुए, उसने खुद आरोप लगाया कि उसके गांव की कुछ महिलाओं के साथ अवैध संबंध थे और वह चाहती थी कि वह उसे हमेशा के लिए छोड़ दे ताकि वह या तो उनके साथ इस तरह का संपर्क कर सके या नए सिरे से शादी कर सके। समान रूप से निंदनीय आरोप यह लगाया गया था कि अपीलकर्ता-

पति के बड़े भाई सरदार सिंह की पत्नी की मृत्यु हो गई थी, वह स्वयं और उसके रिश्तेदारों ने भी उसे सरदार सिंह के साथ सहवास करने या सरदार सिंह की शादी करने की इच्छा जताई थी। अपने पिता के प्रभाव का प्रयोग करके। उपर्युक्त दलीलों पर ट्रायल कोर्ट द्वारा तैयार किया गया सर्वव्यापी मुद्दा निम्नलिखित शब्दों में था: -

(1) क्या याचिकाकर्ता याचिका के पैरा नंबर 4 में बताए गए आधार पर तलाक द्वारा विवाह के विघटन का हकदार है

(२) राहत।

ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता-पति के खिलाफ सामग्री का मुद्दा नंबर 1 पाया, जिसमें एक दृढ़ निष्कर्ष था कि न तो परित्याग का आधार और न ही क्रूरता का आधार जैसा कि याचिका में आरोप लगाया गया था, साबित हुआ। हालांकि, इसके समक्ष यह आग्रह किया गया था कि प्रतिवादी-पत्नी ने अपने लिखित बयान में व्यभिचार का एक जंगली आरोप लगाया था जो प्रति एससी होगा। कानूनी क्रूरता की राशि और इसलिए, अपीलकर्ता-पति अकेले उस स्कोर पर सफल होने का हकदार था। इस स्टैंड को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि यह साबित नहीं हुआ था कि अपीलकर्ता के खिलाफ ये निराधार आरोप याचिका दायर करने से पहले लगाए गए थे और

लिखित बयान में केवल बचाव के माध्यम से किए गए ये क्रूरता नहीं हो सकते। एक आवश्यक परिणाम के रूप में याचिका खारिज कर दी गई थी।

3. अपील पर जब मामला मेरे विद्वान भाई एस. पी. गोयल, जे. के समक्ष आया, तो उपरोक्त तर्क कि लिखित बयान में लगाए गए व्यभिचार का मात्र आरोप मानसिक या कानूनी क्रूरता के बराबर होगा, मुख्य रूप से *श्रीमती जीवन लता* बनाम भारत संघ के आधार पर जोर दिया गया था। *कृष्ण कुमार,* (1)। यह पाते हुए कि *जीवन लता के* मामले में टिप्पणियां अपीलकर्ता के दावे का समर्थन करती हैं और इसके अनुपात की शुद्धता के बारे में संदेह व्यक्त करते हुए, मामले को एक बड़ी बेंच को भेजा गया था।

4. जैसा कि विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष हमारे सामने, अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने याचिका में पहले से ही ली गई क्रूरता और परित्याग की दलीलों का गठन करने वाले तथ्यों पर ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों को चुनौती नहीं दी, जिनकी तदनुसार पुष्टि की जाती है। इस तर्क के लिए कि प्रतिवादी-पत्नी द्वारा अपने बयान में व्यभिचार का घिनौना आरोप, कानूनी क्रूरता की अधिक राशि के बिना होगा और अपीलकर्ता, इसलिए, उसके द्वारा स्थापित मामले को स्थापित करने में उसकी विफलता के बावजूद अकेले इस आधार पर सफल होने का हकदार था, *श्रीमती जीवन लता के* मामले के अनुपात की अनिवार्य रूप से सराहना की गई है। अपीलकर्ता की ओर से स्वीकृति।

5. जिस निर्णय पर बुनियादी भरोसा करने की मांग की गई है, उसका विज्ञापन करने से पहले, पूर्वोक्त तर्क सिद्धांत पर भी कुछ विचार करने योग्य है। मेरे विचार से अंतर्निहित भ्रांति जो यहाँ उत्पन्न हुई प्रतीत होती है, वह इस स्थापित कानूनी स्थिति से उपजी है कि जीवनसाथी के विरुद्ध व्यभिचार का झूठा आरोप कानून की नजर में क्रूरता के समान है। हालांकि, इससे यह अनुमान लगाना दूर की बात होगी कि व्यभिचार का आरोप, चाहे साबित हो या नहीं, अपने आप में कानूनी क्रूरता के गणितीय समकक्ष होगा। ऐसा नहीं है, और मेरे विचार से संभवत कानून नहीं हो सकता है, कि व्यभिचार का तथ्यात्मक रूप से सच्चा आरोप, चाहे वह अन्यथा किया गया हो या लिखित बयान में बचाव में लगाया गया हो, क्रूरता के समान होगा। इस क्षेत्र में इस तरह के आरोप की सच्चाई या अन्यथा मामले की जड़ है। इसलिए, इससे पहले कि व्यभिचार के आरोप को कानूनी क्रूरता के रूप में समझा जा सके, इसे पहले तथ्यात्मक रूप से गलत साबित किया जाना चाहिए। उजागर करने के लिए, यह व्यभिचार का एक स्पष्ट रूप से झूठा आरोप है जो कानूनी क्रूरता के बराबर होगा,

(1) 1979 करंट लॉ जर्नल 509.

और संभवतः उस प्रकृति का सही आरोप नहीं है जो अपमानजनक पति या पत्नी को कार्रवाई का कोई कारण नहीं दे सकता है। एक बार ऐसा होने के बाद, यह प्राथमिक प्रतीत होता है कि व्यभिचार के ऐसे किसी भी आरोप को परीक्षण के लिए रखा जाना चाहिए और यह केवल तभी होता है जब इसकी मिथ्याता या अन्यथा निर्धारित किया जाता है कि कोई कानूनी परिणाम उससे

प्रवाहित हो सकता है। यह वास्तव में यह कहना बहुत दूर की बात होगी कि / केवल एक आरोप और वह भी कानूनी दलीलों में बचाव के माध्यम से किया गया कानून की नजर में कानूनी क्रूरता बन जाना चाहिए और प्रति व्यक्ति तलाक का आधार होना चाहिए। ऐसा प्रस्ताव न तो कानून की भाषा पर और न ही सिद्धांत के आधार पर अनुचित है। इसके अलावा, ऐसा धारण करना व्यभिचार के वैवाहिक अपराध के सच्चे और खुले मुकदमे को अच्छी तरह से निराश कर सकता है क्योंकि 11 अच्छी तरह से एक पति या पत्नी को इस तरह के बचाव को बढ़ाने के लिए रोक सकता है, भले ही यह तथ्यात्मक रूप से परेशान हो।

6. अब कोई श्रीमती जी-वान लता के मामले में दृष्टिकोण * की शुद्धता की जांच कर सकता है जो अपीलकर्ता की ओर से तर्क के लिए आधारशिला प्रदान करता है। निस्संदेह इसमें दी गई टिप्पणियां इस तरह के रुख का समर्थन करेंगी। हालांकि, फैसले के एक करीबी अवलोकन से पता चलता है कि इस विशिष्ट बिंदु पर सिद्धांत पर या मिसाल के संदर्भ में शायद ही कोई चर्चा हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान न्यायाधीश के समक्ष इस मुद्दे पर शायद ही बहस हुई थी और टिप्पणियां पहली छाप पर की गई हैं। ये फिर से बड़े मुद्दे पर पार्टियों के वकील द्वारा रियायत पर आधारित प्रतीत होते हैं कि व्यभिचार का झूठा आरोप प्रकृति और सबूत के तौर-तरीकों के बारे में आगे के विश्लेषण के बिना क्रूरता के बराबर होगा। *अलुंडे* के मामले को दायर करने से पहले या संपार्श्विक कार्यवाही में किए गए व्यभिचार के आरोप और लिखित बयान में बचाव के माध्यम से किए गए इस तरह के आरोप के बीच महत्वपूर्ण अंतर पूरी तरह से खो गया लगता है। जैसा कि पहले ही देखा गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि याचिका दायर करने से पहले लगाए गए व्यभिचार का आरोप और मुद्दा उठाया गया और झूठा पाया गया, कानूनी क्रूरता का गठन करेगा। तथापि, लिखित वक्तव्य में बचाव के रूप में केवल आरोप चाहे वह झूठा हो या अन्यथा हो, उसी श्रेणी में नहीं आता है जब तक कि निस्संदेह, ऐसे मुद्दे पर विशेष रूप से विचारण नहीं किया जाता है और यह ठोस निष्कर्ष निकाला जाता है कि क्या आरोप मिथ्या या प्रमाणित था।

7. अपने द्वारा किए गए निष्कर्ष पर पहुंचने में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने संदर्भित किया और स्पष्ट रूप से *मदन मोहन कोहली* बनाम भारत संघ पर भरोसा किया।श्रीमती *सरला कोहली,* (2), और *श्रीमती दासी* वी। *धनी राम* (3)।

(2) एआईआर 1967~पीबी और हैरी 397?

(3) एआईआर 1969 पीबी और हैरी। 25.

> उन दोनों के विश्लेषण से पता चलता है कि वे याचिका दायर करने से पहले या संपार्श्विक कार्यवाही में किए गए व्यभिचार के आरोप से संबंधित हैं जो पक्षों के बीच मुद्दे पर थे। ये मामले प्राधिकरण के लिए कोई वारंट नहीं हैं कि लिखित बयान में बचाव में किए गए इस प्रकृति के आरोप को इटो प्रूफ या झूठ के बावजूद कानूनी क्रूरता होगी जिसके आधार पर एक याचिकाकर्ता सफल हो सकता है। अपीलकर्ता के विद्वान वकील वास्तव में यह स्वीकार करने के लिए पर्याप्त थे कि उपरोक्त दोनों मामले सीधे बिंदु पर आकर्षित नहीं होते हैं। यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया था कि इस आशय का कोई अन्य अधिकार नहीं था कि व्यभिचार का केवल आरोप स्वयं क्रूरता था, भले ही इसे न तो मुद्दे में रखा गया है और न ही उसके बाद कोशिश की गई है।

> 8. *एसएमएल जीवन लोटा के मामले* में लिया गया दृष्टिकोण, यदि समर्थन किया जाता है, तो जिज्ञासु परिणाम होंगे, यदि नहीं, तो चौंकाने वाले परिणाम होंगे। कोई भी ऐसी स्थिति की कल्पना कर सकता है जहां व्यभिचार का ऐसा आरोप बचाव पक्ष के पति द्वारा लिखित बयान में लगाया जाता है और न तो याचिकाकर्ता और न ही उसके बाद प्रतिवादी ने कोई सबूत पेश किया। *श्रीमती जीवन लता* के मामले के अनुपात पर, भले ही याचिकाकर्ता उसके द्वारा स्थापित मामले को स्थापित करने में पूरी तरह से विफल रहा हो, फिर भी वह केवल इस आधार पर सफल होने का हकदार होगा कि बचाव पक्ष द्वारा व्यभिचार का आरोप लगाया गया था। इस प्रकार याचिका को सफल होना होगा, भले ही याचिकाकर्ता न तो सबूत पेश करता है और न ही अपने मामले को साबित करता है। इस तरह के चौंकाने वाले परिणाम ने वास्तव में *श्रीमती जीवन लता के मामले* में यह सुनिश्चित किया कि अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप साबित नहीं हुए थे, फिर भी तलाक की याचिका को सफल होने दिया गया। इस तरह के परिणाम को आसानी से स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह अच्छी तरह से तय है कि एक याचिकाकर्ता को उसके द्वारा स्थापित मामले में सफल होना चाहिए या गिरना चाहिए।

9. पूरे सम्मान के साथ मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस विशिष्ट बिंदु पर *श्रीमती जीवन लता का मामला* कानून को सही ढंग से निर्धारित नहीं करता है और इसके द्वारा इसे खारिज कर दिया जाता है।

10. प्रतिवादी के विद्वान वकील, श्री चंद्र सिंह के प्रति निष्पक्षता में, हमें ध्यान देना चाहिए कि विकल्प में वह यह तर्क देने की चरम सीमा तक चले गए थे कि प्रतिवादी द्वारा लिखित बयान में बचाव के माध्यम से की गई किसी भी बात को याचिकाकर्ता द्वारा हमले का आधार नहीं बनाया जा सकता है। इसे कानूनी शब्दावली में रखने के लिए यह सुझाव दिया गया है कि लिखित बयान में कथन

व्यभिचार के आरोप को इस अर्थ में विशेषाधिकार प्राप्त होगा कि याचिकाकर्ता इसका कोई लाभ नहीं उठा सकता है। थोड़ी सुरम्य भाषा में प्रतीक के रूप में स्टैंड यह था कि एक ढाल को तलवार में नहीं बदला जा सकता है।

11. मुझे इस चरम प्रस्ताव की सदस्यता लेने में अपनी असमर्थता पर खेद है। यहां तक कि जब, दबाए गए विद्वान वकील इस रुख के समर्थन में कोई अधिकार नहीं दे सकते थे। सिद्धांत रूप में, यह हमें प्रतीत होता है कि इस तरह की चरम स्थिति को गिनना अच्छी तरह से महान सार्वजनिक शरारत कर सकता है। सार रूप में इसका मतलब यह होगा कि बचाव करने वाला पति या पत्नी किसी भी प्रतिशोध के डर से दूसरे के खिलाफ व्यभिचार या अन्य वैवाहिक अपराधों का सबसे गलत आरोप लगा सकता है।

12. पूर्वोक्त स्टैंड की मिथ्याता भी प्रकट होती है जब दूसरे कोण से जांच की जाती है। ऐसा लगता है कि कानून तय हो गया है कि व्यभिचार के पहले या संपार्श्विक आरोप, यदि झूठे हैं, तो तुरंत नाराज पति या पत्नी को कार्रवाई का कारण देंगे। यदि ऐसा है, तो दूसरी याचिका स्पष्ट रूप से एक पति या पत्नी द्वारा झूठ होगी, जिसके खिलाफ पहले की याचिका में व्यभिचार का झूठा आरोप लगाया गया है। वास्तव में प्रतिवादी के विद्वान वकील द्वारा इस स्थिति का बहुत निष्पक्ष रूप से खंडन नहीं किया गया था। यदि दूसरी याचिका में पहले किए गए व्यभिचार के आरोप को कार्रवाई के कारण के रूप में बनाया जा सकता है, तो कोई यह देखने में विफल रहता है कि एक ही कार्यवाही में लिखित बयान में ऐसा आरोप एक अलग स्तर पर क्यों होना चाहिए। प्रतिवादी की ओर से प्रचारित दृष्टिकोण की सदस्यता लेने से केवल कार्यवाही की बहुलता हो सकती है जो हमेशा कानून का इरादा होता है; बचना। इसलिए, मैं किसी भी अमूर्त सिद्धांत की सदस्यता लेने में असमर्थ हूं जो एक लिखित बयान में किए गए व्यभिचार के आरोप के लिए पूर्ण विशेषाधिकार है।

13. एक बार पूर्वोक्त निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद कि व्यभिचार का एक बुरा आरोप कानूनी क्रूरता की राशि नहीं है, यह प्रकट होता है कि इस आधार पर सफल होने के लिए, याचिकाकर्ता को इस तरह के आरोप की असत्यता स्थापित करनी चाहिए। प्रमाण का मृदु, हालांकि, एक नकारात्मक बोझ होने के नाते, नाइटल चरण में एक हल्का होगा। इसलिए, यह आवश्यक हो जाएगा कि ऐसी स्थिति में याचिकाकर्ता को लेटिशन में संशोधन करना होगा और वैवाहिक राहत के लिए एक विशिष्ट आधार के रूप में व्यभिचार के झूठे आरोप की वकालत करनी होगी। यह केवल तभी होता है जब याचिकाकर्ता को हमले का आधार बनाया जाता है

संभवतः इस तरह के आरोप का फायदा उठाएं, अगर गलत साबित हुए। जब तक लिखित बयान में लगाए गए इस तरह के आरोप की सच्चाई या झूठ को पूर्वोक्त तरीके से परीक्षण के लिए नहीं रखा जाता है और इसे एक या दूसरे तरीके से स्थापित नहीं किया जाता है, तब तक अधिनियम की धारा 13 (1) (आईए) के उद्देश्य के लिए कोई कानूनी परिणाम नहीं हो सकता है। इसलिए, ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि न केवल अपेक्षित संशोधन किया जाना चाहिए, बल्कि इसके संबंध में एक विशिष्ट और स्पष्ट मुद्दा तैयार किया जाना चाहिए ताकि पक्षकारों को अपनी आंखें खोलकर मुकदमे में जाना चाहिए। हम वैवाहिक मामलों में सर्वव्यापी मुद्दे को तैयार करने के पक्ष में नहीं देख सकते हैं, जैसा कि इस मामले में तैयार किए गए एकमात्र मुद्दे की स्थिति प्रतीत होती है।

(14) यह प्राथमिक है कि एक याचिका में सफल होने के लिए धारा 13 (1) (आईए) के तहत क्रूरता स्थापित करने का बोझ पति या पत्नी पर है जो ऐसा ही आरोप लगाता है। हालांकि, वर्तमान प्रकृति के मामले में जहां लिखित बयान में बचाव में ऐसा आरोप लगाया गया है, यह एक नकारात्मक बोझ होगा जिसे आसानी से केवल यह कहकर निर्वहन किया जा सकता है कि व्यभिचार का आरोप झूठा है। यह तब व्यभिचार का आरोप लगाने वाले पति या पत्नी के लिए होगा जो इसे प्रमाणित करता है।

अब हमें स्पष्ट रूप से ध्यान देना चाहिए कि अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री अशोक अग्रवाल ने स्पष्ट रूप से प्रार्थना की है कि कानून के पूर्वोक्त दृष्टिकोण पर जो हमने लिया है, उसे अब याचिका में संशोधन करने की अनुमति दी जानी चाहिए और तलाक का दावा करने के आधार के रूप में लिखित बयान में किए गए व्यभिचार के झूठे आरोप को स्पष्ट रूप से बनाया जाना चाहिए। श्रीमती जीवन लता के मामले को खारिज करने के मद्देनजर, अपीलकर्ता के विद्वान वकील यह तर्क देने में त्रुटिहीन आधार पर प्रतीत होते हैं कि कानून के अनुसार कार्य करने के बाद, जैसा कि तब अस्तित्व में था, वह अब पूर्वोक्त प्रकृति के संशोधन की मांग करने के हकदार से अधिक है। इसलिए, हम इस निर्देश के साथ मामले को ट्रायल कोर्ट में भेज देंगे कि अपीलकर्ता को अपनी याचिका में संशोधन करने की अनुमति दी जाए, उस पर एक विशिष्ट मुद्दा तैयार किया जाए, और उसके बाद उसी की कोशिश करने के लिए आगे बढ़ें।

(15) पूर्वोक्त शर्तों में अपील की अनुमति दी जाती है।

S.CX

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

मिताली अग्रवाल
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
रेवाड़ी , हरियाणा